3. उड़ीसा और मध्य प्रदेश में महानदी घाटी कोयला बेसिन (4 परियोजनायें)।

4. मध्य प्रदेश में सोन घाटी बेसिन (2 परियोजनायें)।

5. महाराष्ट्र में वर्धा घाटी कोयला बेसिन।

6. आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी कोयला बेसिन।

7. तमिलनाड में ईस्ट कोस्ट लिग्नाइट फील्ड।

8. राजस्थान और गुजरात में वैस्ट कोस्ट लिग्नाइट फील्ड।

राष्ट्रीय खान नीति

3429. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1993 में एक राष्ट्रीय खान नीति की घोषणा की गई थी जिसके अन्तर्गत यूरेनियम, कोयला और कच्चे तेल के अतिरिक्त अन्य सभी खनिजों के खनन कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति की घोषणा के पश्चात निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थानों ने सरकार के पास अपने-अपने आवेदन भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस नीति की घोषणा करने से पूर्व सरकार द्वारा भारतीय खानों में खनन कार्य करने हेतु विदेशी संस्थानों को आकर्षित करने के लिये अनेक प्रतिनिधि मंडलों को विदेश भेजा गया था ;

(ङ) यदि हां, तो क्या किसी विदेशी उपक्रम द्वारा कोई पेशकश की गई हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि निजी क्षेत्र से अभी तक कोई उत्साहजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस संबंध में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु सरकार की भावी योजनायें क्या हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) राष्ट्रीय खनिज नीति 5 मार्च, 1993 को इस सदन में प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के लिये विशेष रूप से आरक्षित 13 खनिजों का खनन समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) सभी खनिजों के खनन पट्टों के आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत किये जाते हैं, और वे उन पर विचार करती है । यदि माननीय सदस्या, किसी खनिज अथवा राज्य, जिसके बारे में वे जानकारी चाहती हैं, उसका उल्लेख करें, तो उसे संबंधित राज्य सरकार से एकत्र किया जायेगा और सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते ।

3430. *[Transferred* to 23rd *August* 1993]

Irregularities in Steel Development Fund Loans

3431. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of STEEL be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Gov etvunent are likely to lose over Rs. 2000 Crore by way of corporate tax

in the coming years due to evasion by the major steel producing companies through the Steel Development Fund loans-

(b) whether the Development Commissioner for Iron and Steel has, in its report on the ratioualisation of SDF has commented upon the irregu larities into the system and procedures; of operating the Fund;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what action is contemplated by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRl SONTOSH MOHAN DEV): (a) Loans from the Steel Development Fund (SDF) are given to the steel producers for financing schemes, projects and capital expenditure for moodertii-sation, diversification and improvement of the technology and efficciency of iron and steel production. Grant of loans from SDF does not lead to evasion of tax by the steel producers.

(b) and (c) No, Sir. The Development Commissioner for Iron and Steel has submitted an internal report on the rationalisation of SDF in which certain suggestions have been made for imroving the operational procedures of the Fund.

(d) Does not arise.

Durgapur Steel Plant

3432. MISS; SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Durgapur Steel Plant is Sick unit of the Steel Authority of India Limited; and

(b) if so, what steps have been taken to revive/modernise the units?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) Durgapur Steel Plant is one of the units of Steel Authority of India Limited (SAIL). While SAIL is earning profit coutinuously from 1934-85, its unit i.e. Durgapur Steel plant has been making losses mainly due to outdated technology.

(b) Steel Authority of India limi ted have taken several steps to im prove the performance and profitabi lity of Durgapur Steel Plant. SAIL has embarked on a massive Renova tion and Technological Upgradation (Modernisation) of DSP, with the objective of improving productivity, reducing the cost of production and improving the quality of products. Other Steps taken to improve operations of DSP include improving the product-mix in line with the market demand, improvement in the yield of bye products, optimising captive power generation, reducing energy consumption, vigorous implementation of budgetary control system, etc.

Resignationi of officials in SAIL

3433. SHRl V. NARAYANASAMY: Will the Minister of STEEL be pleased to state;

(a) whether it is a fact that several top officials of the Steel Authority of India Limited have resigned in protest against the new promotion policy; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) No, Sir. It is not a fact that several top officials of the Steel Authority of India Limited have resigned in protest against the new promotion policy.

(b) Does not arise.